

---

**Q. Discuss the procedure for the impeachment of a High Court judge in India. How does it ensure accountability and judicial independence?**

The impeachment of a High Court judge ensures accountability while safeguarding judicial independence. The Constitution provides a detailed process under Articles 124(4) and 218, with procedural elaboration in the Judges (Inquiry) Act, 1968.

**Procedure for Impeachment**

1. **Initiation of Motion:**
  - A motion requires signatures from **100 members in Lok Sabha** or **50 members in Rajya Sabha**.
  - The motion is submitted to the Speaker or Chairman, who may admit or reject it.
2. **Formation of Inquiry Committee:**
  - If admitted, a **three-member committee** is constituted comprising:
    - Chief Justice of India or a Supreme Court judge.
    - Chief Justice of a High Court.
    - A distinguished jurist.
  - The committee investigates charges and submits its findings.
3. **Parliamentary Voting:**
  - Both Houses must pass the motion with:
    - A **majority of total membership**.
    - A **two-thirds majority of members present and voting**.
4. **Presidential Approval:**
  - After parliamentary approval, the President issues an order for removal.

Investigations into judicial misconduct ensure adherence to the highest ethical standards by subjecting allegations to thorough examination. The parliamentary debate and voting process reinforce public trust by maintaining transparency, ensuring that the proceedings are fair and not arbitrary. Moreover, the impeachment process acts as a deterrent against judicial misconduct, thereby upholding the integrity and credibility of the judiciary as a crucial institution in a democratic setup. Moreover, the impeachment procedure incorporates a high threshold for removal, requiring a two-thirds majority of members present and voting in both Houses of Parliament. This high standard ensures protection against frivolous or politically motivated motions. Additionally, the inclusion of senior judicial members in the inquiry committee guarantees a fair and impartial investigation, preserving the neutrality and independence of the judiciary throughout the process.

While no High Court judge has been successfully impeached, the robust framework ensures a balance between accountability and independence, integral to upholding democracy and the rule of law. Strengthening internal judicial ethics mechanisms alongside the impeachment process can further enhance institutional trust.

**प्रश्न भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया पर चर्चा करें। यह जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करता है?**

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित होती है। संविधान में अनुच्छेद 124(4) और 218 के तहत विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान है, साथ ही न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में प्रक्रियात्मक विस्तार भी दिया गया है।

### **महाभियोग की प्रक्रिया**

1. प्रस्ताव की शुरूआत:
  - a. प्रस्ताव पर लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।
  - b. प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत किया जाता है, जो इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
2. जांच समिति का गठन:
  - a. यदि स्वीकार किया जाता है, तो तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - i. भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
    - ii. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
    - iii. एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता
  - b. समिति आरोपों की गहन जांच करती है और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करती है।
3. संसदीय मतदान:
  - a. दोनों सदनों को प्रस्ताव को निम्नलिखित बहुमत से पारित होना चाहिए:
    - i. सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
    - ii. उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
4. राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति:
  - a. संसदीय स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करता है।

न्यायिक कदाचार की जांच आरोपों की गहन जांच करके उच्चतम नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करती है। संसदीय बहस और मतदान प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखते हुए जनता के विश्वास को मजबूत करती है। साथ ही, यह सुनिश्चित करती है कि कार्यवाही निष्पक्ष हो और मनमानी न हो। इसके अलावा, महाभियोग प्रक्रिया न्यायिक कदाचार के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करती है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में न्यायपालिका की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखा जाता है। इसके अलावा, महाभियोग प्रक्रिया में निष्कासन के लिए कठोर प्रावधान शामिल है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यह उच्च मानक राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्तावों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, जांच समिति में वरिष्ठ न्यायिक सदस्यों को शामिल करने से निष्पक्ष जांच की गारंटी मिलती है, जिससे पूरी प्रक्रिया के दौरान न्यायपालिका की तटस्थता और स्वतंत्रता बनी रहती है।

हालांकि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अभी तक सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं लगाया गया है, लेकिन मजबूत ढांचा जवाबदेही और स्वतंत्रता के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है, जो लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है। महाभियोग प्रक्रिया के साथ-साथ आंतरिक न्यायिक नैतिकता तंत्र को मजबूत करने से संस्थागत विश्वास को और बढ़ाया जा सकता है।